Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

OVERVIEW

After the end of the bipolar structure of world politics in the early 1990s, it became clear that alternative centres of political and economic power could limit America's dominance. Thus, in Europe, the European Union (EU) and, in Asia, the Association of South East Asian Nations (ASEAN), have emerged as forces to reckon with. While evolving regional solutions to their historical enmities and weaknesses, both the EU and the ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economies. The economic rise of China has made a dramatic impact on world politics. In this chapter, we take a look at some of these emerging alternative centres of power and assess their possible role in the future.

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो-ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनैतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमरीका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान, दोनों ने ही अपने-अपने इलाके में चलने वाली एतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढ़ा । साथ ही इन्होंने अपने-अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केन्द्रों पर एक नज़र डालेंगे और यह जाँचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

EUROPEAN UNION

As the Second World War came to an end, many of Europe's leaders grappled with the 'Question of Europe'. Should Europe be allowed to revert to its old rivalries or be reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? The Second World War shattered many of the assumptions and structures on which the European states had based their relations. In 1945, the European states confronted the ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been

यूरोपीय संघ

जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता 'यूरोप के सवालों' को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए? दूसरे विश्वयुद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

European integration after 1945 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the 'Marshall Plan'. The US also created a new collective security structure under NATO. Under the Marshall Plan, the Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) was established in 1948 to channel aid to the west European states. It became a forum where the western European states began to cooperate on trade and economic issues.

1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल-मिलाप को शीतयुद्ध से भी मदद मिली। अमरीका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने 'नाटो' के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक एसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक-दूसरे की मदद शुरू की।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The Council of Europe, established in 1949, was another step forward in political cooperation. The process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step (see Timeline of European Integration) leading to the formation of the European Economic Community in 1957. This process acquired a political dimension with the creation of the European Parliament.

1949 में गठित यूरोपीय परिषद् राजनैतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी (इस एकीकरण का कालक्रम देखें) और इसके परिणामस्वरूप 1957 में यूरोपीयन इकॉनामिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीयन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992. The foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and the creation of a single currency.

सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आयी और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एकसमान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one. The EU has started to act more as a nation state. While the attempts to have a Constitution for the EU have failed, it has its own flag, anthem, founding date, and currency. It also has some form of a common foreign and security policy in its dealings with other nations.

एक लम्बे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनैतिक रूप लेता गया है। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट–राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हाँलाकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना–दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the erstwhile Soviet bloc. The process has not proved easy, for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their country. There are also reservations about including some new countries within the EU

नये सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नये सदस्य मुख्यत: भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ ख़ास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The EU has economic, political and diplomatic, and military influence. The EU is the world's second biggest economy with a GDP of more than $17 trillion in 2016, next to that of the United States of America. Its currency, the euro, can pose a threat to the dominance of the US dollar. Its share of world trade is much larger than that of the United States allowing it to be more assertive in trade disputes with the US and China.

यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17000 अरब डालर से ज़्यादा था जो अमरीका के ही लगभग है। इसकी मुद्रा यूरो अमरीकी डालर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमरीका से तीन गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमरीका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Its economic power gives it influence over its closest neighbours as well as in Asia and Africa. It also functions as an important bloc in international economic organisations such as the World Trade Organisation (WTO).

इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं, बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर-दराज के मुल्क़ों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्त्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The EU also has political and diplomatic influence. Two members of the EU, Britain and France, hold permanent seats on the UN Security Council. The EU includes several non-permanent members of the UNSC. This has enabled the EU to influence some US policies such as the current US position on Iran's nuclear programme.

यूरोपीय संघ के दो सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमरीका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमरीकी नीतिया को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Its use of diplomacy, economic investments, and negotiations rather than coercion and military force has been effective as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation.

चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Militarily, the EU's combined armed forces are the second largest in the world. Its total spending on defence is second after the US. Two EU member states, Britain and France, also have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads. It is also the world's second most important source of space and communications technology.

सैनिक ताकत के हिसाब से य्रोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमरीका के बाद सबसे अधिक है। य्रोपीय संघ के दो देशों – ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इनके ज़खीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी य्रोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

As a supranational organisation, the EU is able to intervene in economic, political and social areas.

अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है।

Alternative Centres of Power
सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Alternative Centres of Power
सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Alternative Centres of Power
सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The cartoon appeared in 2003 when the European Union's initiative to draft a common Constitution failed. Why does the cartoonist use the image of the ship Titanic to represent EU?

2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक ज़हाज के रूप में क्यों दिखाया है?

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

Take a look at the political map of the world. Which countries would you say fall in the southeastern region of Asia? Before and during the Second World War, this region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialisms, both European and Japanese. At the end of the war, it confronted problems of nation-building, the ravages of poverty and economic backwardness and the pressure to align with one great power or another during

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान)

दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें। आपके ख़्याल से कौन-से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान, एशिया का यह हिस्सा बार-बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनैतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट-निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीतयुद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झलना पड़ा।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

This was a recipe for conflict, which the countries of Southeast Asia could ill afford. Efforts at Asian and Third World unity, such as the Bandung Conference and the Non-Aligned Movement, were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. Hence, the Southeast Asian alternative by establishing the Association of South East Asian Nations (ASEAN).

टकरावों और भागमभाग की एसी स्थिति को दक्षिण–पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण–पूर्व एशियाई संगठन (आसियान) बनाकर एक वैकल्पिक पहल की।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

ASEAN was established in 1967 by five countries of this region — Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand — by signing the Bangkok Declaration. The objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that 'social progress and cultural development'. A secondary objective was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of the United Nations Charter. Over the years, Brunei Darussalam, Vietnam, Lao PDR, Myanmar (Burma) and Cambodia joined ASEAN taking its strength to ten.

1967 में इस क्षेत्र के पाँच देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 'आसियान' की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 'आसियान' का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या दस हो गई।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Unlike the EU there is little desire in ASEAN for supranational structures and institutions. ASEAN countries have celebrated what has become known as the 'ASEAN Way', a form of interaction that is informal, nonconfrontationist and cooperative. The respect for national sovereignty is critical to the functioning of ASEAN.

यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल-मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है और इसको 'आसियान शैली' (**ASEAN way**) ही कहा जाने लगा है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objectives beyond the economic and social spheres. In 2003, ASEAN moved along the path of the EU by agreeing to establish an ASEAN Community comprising three pillars, namely, the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural Community.

दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक–सांस्कृतिक समुदाय नामक तीन स्तम्भों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता–जुलता है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The ASEAN security community was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. The ASEAN Regional Forum (ARF), which was established in 1994, is the organisation that carries out coordination of security and foreign policy.

आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, अहस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच (**ARF**) की स्थापना की गई।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

ASEAN was and still remains principally an economic association. While the ASEAN region as a whole is a much smaller economy compared to the US, the EU, and Japan, its economy is growing much faster than all these. This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond. The objectives of the ASEAN Economic Community are to create a common market and production base within ASEAN states and to aid social and economic development in the region.

बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह एसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमरीका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाज़ार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The Economic Community would also like to improve the existing ASEAN Dispute Settlement Mechanism to resolve economic disputes. ASEAN has focused on creating a Free Trade Area (FTA) for investment, labour, and services. The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN.

यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र (**FTA**) बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमरीका और चीन ने कर भी दी है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The current economic strength of ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing Asian economies such as India and China, makes this an attractive proposition. During the Cold War years Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. But in recent years, India has tried to make amends. It signed trade agreements with three ASEAN members, Malaysia, Singapore and Thailand.

आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति, खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधाारने की कोशिश की है। भारत ने दो आसियान सदस्यों, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The ASEAN-India FTA came into effect in 2010. ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction and consultation with member states, with dialogue partners, and with other nonregional organisations. It is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns.

2010 में आसियान–भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर–क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र एसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनैतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनैतिक मंच उपलब्ध कराता है।

Alternative Centres of Power
सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

THE RISE OF THE CHINESE ECONOMY

Let us now turn to the third major alternative centre of power and our immediate neighbour, China China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. China has been the fastest growing economy since the reforms first began there. It is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040.

चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान

आइए, अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख़ करें। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, अमरीका से भी आगे निकल जाएगा।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Its economic integration into the region makes it the driver of East Asian growth, thereby giving it enormous influence in regional affairs. The strength of its economy, together with other factors such as population, land mass, resources, regional location and political influence, adds to its power in significant ways.

आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन–जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भू–भाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनैतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढा देते हैं।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

After the inception of the People's Republic of China in 1949, following the communist revolution under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. The economically backward communist China chose to sever its links with the capitalist world. It had little choice but to fall back on its own resources and, for a brief period, on Soviet aid and advice. The model was to create a state-owned heavy industries sector from the capital accumulated from agriculture. As it was short of foreign exchange that it needed in order to buy technology and goods on the world market, China decided to substitute

1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहां की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूँजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड लिए। एसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। हां, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूँजी निकाल कर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चूंकि इसके पास विदेशी बाज़ारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे-धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

This model allowed China to use its resources to establish the foundations of an industrial economy on a scale that did not exist before. Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them. The economy also grew at a respectable rate of 5-6 per cent.

इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6 फीसदी की दर से हुआ।

But an annual growth of 2-3 per cent in population meant that economic growth was insufficient to meet the needs of a growing population. Agricultural production was not sufficient to generate a surplus for industry. In Chapter 2, we discussed the crisis of the state controlled economy in the USSR. A similar crisis was to face China too: its industrial production was not growing fast enough, international trade was minimal and per capita income was very low.

लेकिन जनसंख्या में 2–3 फीसदी की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय दो में हम सोवियत संघ की राज्य–नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। एसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The Chinese leadership took major policy decisions in the 1970s. China ended its political and economic isolation with the establishment of relations with the United States in 1972. Premier Zhou Enlai proposed the 'four modernisations'(agriculture, industry, science and technology and military) in 1973. By 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the 'open door' policy and economic reforms in China. The policy was to generate higher productivity by investments of capital and

चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमरीका से संबंध बनाकर अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाऊ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के चार प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्याओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और 'खुले द्वार की नीति' की घोषणा की। अब नीति यह हो गयी कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाज़ारमूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

China followed its own path in introducing a market economy. The Chinese did not go for 'shock therapy' but opened their economy step by step. The privatisation of agriculture in 1982 was followed by the privatisation of industry in 1998. Trade barriers were eliminated only in Special Economic Zones (SEZs) where foreign investors could set up enterprises. In China, the state played and continues to play a central role in setting up a market economy.

चीन ने 'शॉक थेरेपी' पर अमल करने के बज़ाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' के लिए ही हटाया गया है जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते है

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The new economic policies helped the Chinese economy to break from stagnation. Privatisation of agriculture led to a remarkable rise in agricultural production and rural incomes. High personal savings in the rural economy lead to an exponential growth in rural industry. The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at a faster rate. The new trading laws and the creation of Special Economic Zones led to a phenomenal rise in foreign trade

नयी आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि–उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि–दर तेज रही। व्यापार के नये कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन– SEZ) के निर्माण से विदेश–व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

China has become the most important destination for foreign direct investment (FDI) anywhere in the world. It has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. China's accession to the WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world. The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future world economic order.

चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक क़दम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The Great Wall and Dragon are two symbols most commonly associated with China. This cartoon uses both these to depict China's economic rise. Who do you think is the little man in this cartoon? Can he stop the dragon?

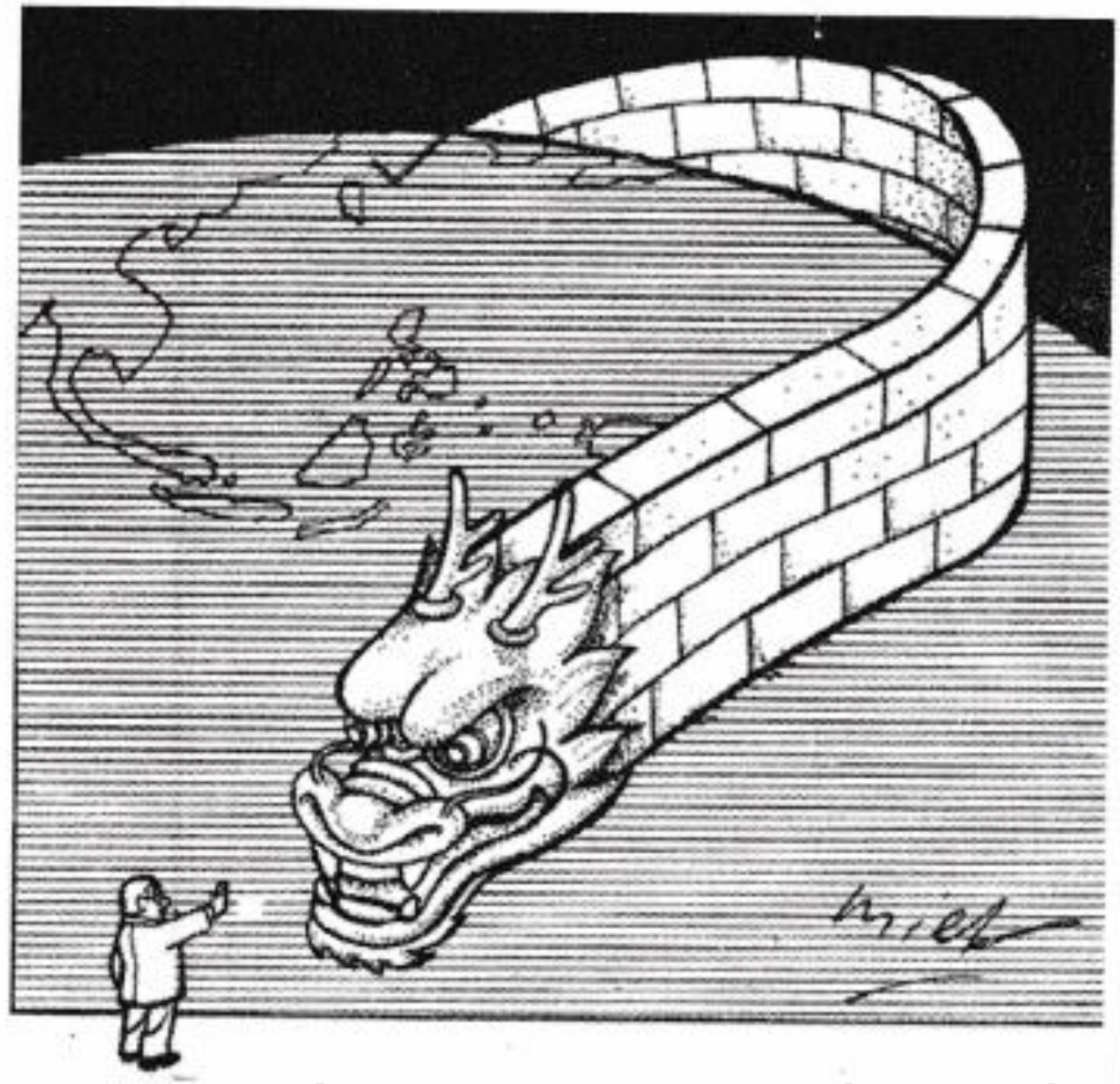

चीन की बढ़ती ताकत

अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जेहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौंधती है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहां कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचानिए कि कार्टून में दिखाया गया एक छोटा-सा आदमी कौन हो सकता है? क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है?

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

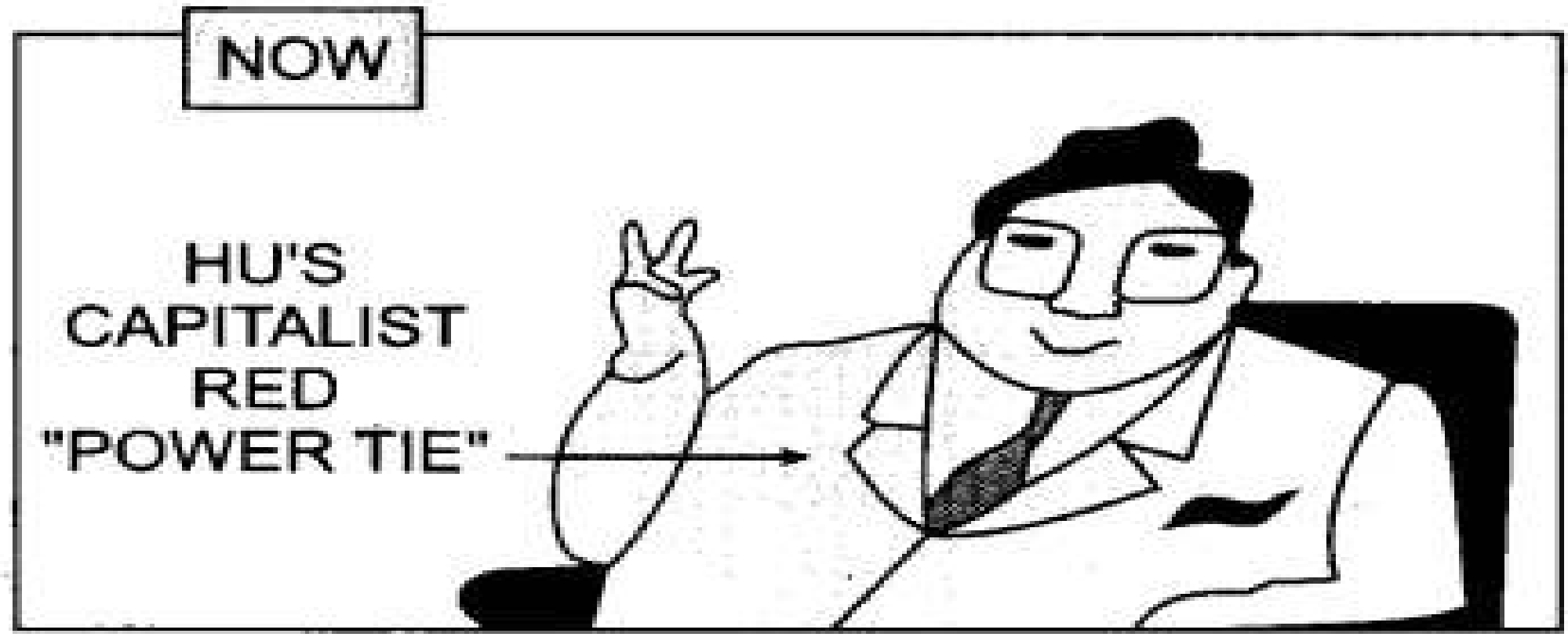

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

कार्टून

केगल्स

ऐस

© Ares, Cagle Cartoons Inc.

Chinese bicycle

चीनी साइकिल

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

INDIA – CHINA RELATIONS

India and China were great powers in Asia before the advent of Western imperialism. China had considerable influence and control on the periphery of its borders based on its unique tributary system. At different times in China's long history of dynastic rule, Mongolia, Korea, parts of Indo-China, and Tibet accepted China's authority. Various kingdoms and empires in India also extended their influence beyond their borders.

चीन के साथ भारत के संबंध

पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नज़राना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लम्बे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिन्द–चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधोनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

In both cases this influence was political, economic and cultural. However, the regions where India and China exercised influence rarely ever overlapped. Thus, there was limited political and cultural interaction between the two. The result was that neither country was very familiar with the other. In the twentieth century, when both nations confronted each other, they had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other.

भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनैतिक नहीं था – यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब बीसवीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक-दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

After India regained its independence from Britain, and China expelled the foreign powers, there was hope that both would come together to shape the future of the developing world and of Asia particularly. For a brief while, the slogan of 'Hindi-Chini bhaibhai' was popular. However, military conflict over a border dispute between the two countries marred that hope. Soon after independence.

अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए 'हिंदी–चीनी भाई–भाई' का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया।

both states were involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of the Sino-Indian border. China and India were involved in a border conflict in 1962 over competing territorial claims principally in Arunachal Pradesh and in the Aksai Chin region of Ladakh.

आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत–चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई–चिन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड पड़े।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

The conflict of 1962, in which India suffered military reverses, had long-term implications for India–China relations. Diplomatic relations between the two countries were downgraded until 1976. Thereafter, relations between the two countries began to improve slowly. After the change in China's political leadership from the mid to late 1970s, China's policy became more pragmatic and less ideological. So it was prepared to put off the settlement of contentious issues while improving relations with India. A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981.

1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झलनी पड़ी और भारत–चीन सम्बन्धों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धोरे–धोरे दोनों के बीच सम्बन्धों में सुधार शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की ृंखला भी शुरू की गई।

Alternative Centres of Power सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र

Since the end of the Cold War, there have been significant changes in India–China relations. Their relations now have a strategic as well as an economic dimension. Both view themselves as rising powers in global politics, and both would like to play a major role in the Asian economy and politics.

शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद से भारत–चीन संबंधों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व–राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे।